हिन्दी दैनिक

आर.एन.आई.नं.:-UPHIN/2005/16132

उपभोक्ता की दुनिया

श्रावस्ती से प्रकाशित

वर्ष : 21 अंक : 06 | श्रावस्ती, गुरूवार 12 जून 2025 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : 1 रूपया

राज्य के २८,८३० चौराहों का कायाकल्प करेगी योगी सरकार, राजमार्गों की चौड़ाई बढ़ाकर कम से कम दो लेन की जाएगी

लखनऊ (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश को उत्तम कनेक्टिविटी युक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार प्रदेश में 2000 रुपए की धनराशि खर्च कर 28,830 चौराहों का कायाकल्प करेगी। सीएम योगी के निर्देशों को ध्यान में रखकर लोकनिर्माण विभाग द्वारा इस विषय में एक खाका तैयार किया गया है। इसके अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2021–24 के बीच 1435 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक व अल्पकालिक सुधार कार्यों को पूरा किया गया है। वहीं, प्रदेश में बड़े स्तर पर दो लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को न्यूनतम दो लेन (पेव्ड शोल्डर युक्त) करने की तैयारी है, जिससे पैदल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही, 50 किमी से अधिक लंबाई वाले राज्यमार्गों पर ट्रक ले–बाई के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने की तैयारी है। इन सभी कार्यों के जरिए प्रदेश में रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने और यातायात सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार, ऐसे राज्य मार्ग जिनकी चौड़ाई 2 लेन से कम है या फिर दो लेन होने के बावजूद वहां पेव्ड शोल्डर कार्यों को पूरा नहीं किया गया है उसे पूरा करने पर योगी सरकार का फोकस है। प्रक्रिया के जरिए 748 करोड़ रुपए की लागत से 895 पेव्ड शोल्डर की चौड़ाई के कार्यों को पूरा किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी राज्यमार्ग कम से कम 2 लेन चौड़े तथा पेव्ड शोल्डर युक्त हों जिससे पैदल यात्रियों व साइकिल इत्यादि से चलने वाले राहगीरों की सुविधा व सुरक्षा में इजाफा होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत 50 किमी से अधिक लंबाई वाले राज्यमार्गों पर ट्रक ले–बाई के निर्माण कार्य को पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए कुल 102 कार्य निर्धारित हैं, जिसके जरिए 8,887.88 किमी की लंबाई पर इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में ऐसे स्थान जहां यातायात परिवहन की वास्तविक गति उसने निर्माण के दौरान प्रस्तावित डिजाइन गति से 50 प्रतिशत या कम है, ऐसे सभी मार्गों को चिह्नित कर लिया गया है। इन मार्गों पर मेजर जियोमेट्रिकल इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा जिससे न केवल यातायात परिवहन की गति में सुधार होगा बल्कि सुगम व सुरक्षित यातायात को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार, प्रदेश के 28,830 विभिन्न चौराहों, तिराहों और महत्वपूर्ण रोड जंक्शंस पर सुधार कार्यों को 2000 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरा किए जाने की तैयारी है। यहां दीर्घकालिक व अल्पकालिक सुधार कार्यों समेत रोड सेफ्टी के विभिन्न मानकों के अनुरूप कार्रवाई होगी। प्रदेश के सभी 1,435 ब्लैक स्पॉट्स को पहले ही चिह्नित करके वहां रोड सेफ्टी मेजर्स को लागू किया जा चुका है और ऐसे स्थानों को चिह्नित करके उन पर भी सुधार कार्य किया जा रहा है जो जोखिम संभावित क्षेत्र में परिवर्तित हो सकते हैं।

मोदी सरकार ने ३ राज्यों को दी बड़ी सौगात, ६,४०० करोड़ रुपए की २ रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी

नयी दिल्ली (एजेन्सी) केंद्र सरकार ने आज बुधवार को रेलवे ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। इनमें झारखंड के चार जिलों और कर्नाटक–आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को कवर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक लागत घटेगी, यात्रा सुगम होगी, और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे हरित व टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि झारखंड में कोडरमा से बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को डबल किया जाएगा, जिसकी लागत 3,063 करोड़ रुपए है। यह परियोजना पटना और रांची के बीच दूरी कम करने में सहायक होगी और कोडरमा, चतरा, हजारीबाग व रामगढ़ जिलों को बेहतर रेल संपर्क देगी। वैष्णव ने बताया, "इस परियोजना से करीब 15 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, साथ ही 938 गांवों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सालाना 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत और 30.4 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता इसे आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी बनाती है। दूसरी प्रमुख परियोजना के तहत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच बल्लारी–चिकजाजुर सेक्शन को डबल किया जाएगा। यह 185 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जिस पर 3,342 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इस सेक्शन की डबलिंग से मंगलुरु पोर्ट तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और माल परिवहन की गति बढ़ेगी। यह

परियोजना दक्षिण भारत में औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक मानी जा रही है। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "आईआईएम बैंगलोर और कलकत्ता के एक अध्ययन से पता चला है कि परिवहन ढांचे में निवेश से देश की लॉजिस्टिक्स लागत में 4 फीसदी तक की गिरावट आई है।

केंद्र सरकार बताए भारत-पाक सीजफायर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी : संजय राउत

मुंबई (एजेन्सी) भारत–पाक सीजफायर को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार की ओर से यह नहीं बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में सीजफायर नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने मंगलवार को सातों सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस मुलाकात में पीएम मोदी ने बारी–बारी सभी सांसदों से उनके अनुभव को समझा। पीएम मोदी और सातों प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की मुलाकात पर जब शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत से बुधवार को मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, ष्प्रधानमंत्री मोदी ऐसे आयोजन करते रहते हैं। लेकिन, प्रधानमंत्री ने अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ, वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुआ है या नहीं। देश यह जानना चाहता है। क्योंकि, अब तक 15 बार ट्रंप ने कहा कि उसने पीएम मोदी पर दबाव बनाया कि सीजफायर की घोषणा की जाए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विदेश गए, और लौटने पर पीएम मोदी से मुलाकात की। लेकिन, देश जानना चाहता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में सीजफायर हुआ। अगर यह चर्चा पीएम मोदी और प्रतिनिधिमंडल में हुई है, तो मैं इसे महत्व दूंगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से केंद्र सरकार की पीओके मुद्दे पर आलोचना करने पर संजय राउत ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के मन में एक चीज थी कि अब मोदी पीओके ले लेंगे और पाकिस्तान को ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान वापस नहीं उठ पाएगा। पाकिस्तान चार टुकड़ों में बंट जाएगा। हम देख रहे थे कि हम लाहौर जाएंगे, हम कराची जाएंगे, एक अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत होगा। हमें उम्मीद थी कि पीएम मोदी वीर सावरकर के सपने को साकार करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ। संजय राउत ने कहा कि जब हम यूएस जाएंगे, तो ट्रंप से

बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आपने पीएम मोदी पर सीजफायर के लिए दबाव क्यों डाला। प्रतिनिधिमंडल तो सवाल पूछ नहीं सकते हैं। हम पूछ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि महाकुंभ में सरकारी डाटा से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जब इस पर संजय राउत से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कुंभ में हजारों लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोग लापता हो गए। जिसका कोई पता नहीं चल सका है।

७८ के हुए लालू प्रसाद यादव : हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन और सम्राट चौधरी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नयी दिल्ली (एजेन्सी) राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बुधवार को अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूर्व सीएम के जन्मदिन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शुभकामनाएं दी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लालू और तेजस्वी के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा, राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे भारतीय राजनीति की अग्रणी शक्ति रहे हैं, जिन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों को सत्ता के केंद्र में रखा। मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को मजबूती से आगे बढ़ाकर और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर उन्होंने सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय विमर्श को नया रूप दिया। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजद सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं।"तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके दीर्घायु होने की कामना की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं।" लालू यादव की

बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को अपना आदर्श बताया। एक्स पर रोहिणी ने लिखा, ष्हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा, हमारी ताकत, हमारे कवच, हमारे आदर्श, हमारे गौरव, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सुपरमैन, हमारे पापा को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे पापा। वहीं, समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से आपकी दीर्घायु एवं सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहने की प्रार्थना है।"

भाजपा के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी : अखिलेश यादव

लखनऊ (एजेन्सी) समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक एक्स–रे का वीडियो जारी कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी ही है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा, यह भाजपा के कुशासन का एक्स–रे है। भाजपा के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी ही है। यह गंभीर जांच का विषय है कि कहीं ये असंभव कागजी एक्स–रे किसी और के मूल एक्स–रे की फोटोकॉपी तो नहीं, इसे किसी और का बताकर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही हो और गलत चिकित्सा–उपचार भी किया जा रहा हो। तुरंत जांच पर जांच बैठाई जाए, और सच्ची रिपोर्ट बाहर लाई जाए। वीडियो के नीचे कैप्शन में लिखा है कि योगी जी के शासन में कमाल की एक्स–रे रिपोर्ट कागज में दी जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को हिदायत देते हुए कहा कि इधर–उधर की राजनीति छोड़कर अपने मंत्रालय पर ध्यान दें। कागज में एक्स–रे की रिपोर्ट सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज की बताई जा रही है, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसके पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, क्या आपने कभी कागज के पन्ने पर एक्स–रे फिल्म ली है? नहीं तो सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज में आइए, यहां कई सालों से कागज के पन्ने पर एक्स–रे मिलता है। कोई नियमित रेडियोलॉजिस्ट भी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली फर्जी भाषणों से दूर नहीं होगी। भाजपा मतलब बर्बादी। इसके अलावा सपा मुखिया ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि भाजपा में जो लोग अपने समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने के बाद उपेक्षित किए जाने के 'साक्षी' हैं, वे जब सच्चे मन से बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं। उनके बयान और भाषण भाजपा को अंतिम चुनौती नहीं हैं बल्कि भविष्य का उद्घोष हैं क्योंकि वे भी जानते हैं कि 'पीडीए' ही उनका स्वाभाविक और स्थायी पड़ाव है, जहां हर पीडीए से सच्चा लगाव है। बाकी क्या कहना, वे स्वयं और उनका समाज स्वयं ही अपने मान–सम्मान को लेकर बेहद जागरूक, सक्रिय और समझदार है। थोड़े लिखे को ज्यादा समझिएगा।

प्रधानमंत्री ने की ३३ बड़ी गलतियां, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला हमला

नयी दिल्ली (एजेन्सी) केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 11 साल के कार्यकाल में 33 बड़ी गलतियां करने का आरोप लगाया और कहा कि मैंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोले और जनता को गुमराह करे। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा, "मैं 55 वर्षों तक सत्ता में रहा हूं और 65 वर्षों से राजनीति में हूं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो इतनी गलतियां करे, झूठ बोले और युवाओं को धोखा दे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लोगों को वोट के लिए फंसाते हैं, गरीबों से झूठे वादे करते हैं और कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी, रोजगार सृजन, और एमएसपी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार ने सिर्फ वादे किए, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री हर बात पर झूठ बोलते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी कभी यह स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने कोई गलती की है, न ही इसके लिए कभी देश से माफी मांगी।

"वो एक के बाद एक वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें निभाते नहीं हैं।" गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। इसी के साथ उनकी सरकार ने सोमवार को 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सरकार के इस कार्यकाल को विफलताओं से भरा मान रही है।

सबूतों से हुआ सामना तो टूट गई सोनम! कबूला पति की हत्या का जुर्म

मिली जानकारी के मुताबिक, राजा रघुवंशी मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने जब सोनम को सबूत दिखाए तो वह टूट गई

इंदौर (एजेन्सी)। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले ने पूरे देश का हिलाकर रख दिया है। राजा की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुई सोनम को मेघालय पुलिस शिलांग लेकर गई है। इसके अलावा इन मामले में शामिल अन्य चार आरोपियों को भी अपने साथ लेकर गई है। पुलिस इस मामले में लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि, सोनम ने पुलिस के सामने अपराध कबूल कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, राजा रघुवंशी मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने जब सोनम को सबूत दिखाए तो वह टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि राजा की हत्या में शामिल है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए ईस्ट खासी हिल्स के एडिशनल एसपी आशीष ने बताया, आज संदिग्धों को कोर्ट में भेजने के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है। इसलिए हमें उनसे पूछताछ करने का समय नहीं मिला। इस बात की प्रबल संभावना है कि वह (सोनम रघुवंशी) इसमें शामिल है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि जांच लंबित है। हम शुरुआती चरण में हैं। जैसे ही हमें नई जानकारी मिलेगी, हम उसे साझा करेंगे... अभी जो भी जानकारी (सार्वजनिक डोमेन में है) वह ठोस नहीं है। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सायम ने कहा कि हम अभी आरोपी को यहां लेकर आए हैं। अब गहन जांच शुरू होगी। हमारे पास उसकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं। पूरी तस्वीर के बारे में – उसकी संलिप्तता कितनी थी और उसने क्या किया – यह सब बाद में पता चलेगा। इससे पहले मेघालय पुलिस की जांच में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई थी वह यह थी कि राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी और अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात की थी। फिर वह वाराणसी गई और उसके बाद

गाजीपुर के नंदगंज में पकड़ी गई। इस बीच, शिलांग पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के साथ ही अन्य आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले गई है। गाजीपुर में आत्मसमर्पण करने के बाद सोनम ने कहा था कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मेघालय से यूपी लाया गया था। लेकिन मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया है कि 23 मई को पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी चली गई थी। वहां से ट्रेन से वह 25 मई को इंदौर पहुंची और राज कुशवाहा से मिली। दोनों किराए के एक कमरे में एक साथ रुके। अगले दिन राज ने एक कार से सोनम को उत्तर प्रदेश भेज दिया। राज की योजना सोनम को फतेहपुर जिले में अपने पैतृक गांव में रुकवाने की थी।

भारत का कोयला आयात अप्रैल में ४.४: घटकर २.४९५ करोड़ टन

नयी दिल्ली (एजेन्सी) भारत का कोयला आयात अप्रैल में 4.4 प्रतिशत घटकर 2.495 करोड़ टन रह गया। अप्रैल 2024 में यह 2.610 करोड़ टन रहा था। बी2बी ई–कॉमर्स कंपनी एमजक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 के 2.279 करोड़ टन के मुकाबले अप्रैल में कोयले का आयात 9.48 प्रतिशत अधिक रहा। अप्रैल में कुल आयात में से गैर–कोकिंग कोयले का आयात 1.590 करोड़ टन रहा, जबकि पिछले वर्ष अप्रैल में यह 1.740 करोड़ टन रहा था। कोकिंग कोयले का आयात 54.2 लाख टन रहा, जो अप्रैल 2024 में 49.7 लाख टन रहा था।

देश का घरेलू कोयला उत्पादन अप्रैल में 3.6 प्रतिशत बढ़कर 8.157 करोड़ टन हो गया। अप्रैल 2024 में भारत का घरेलू कोयला उत्पादन 7.871 करोड़ टन रहा था। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा, '' अप्रैल 2025 के दौरान भारत में कुल कोयला उत्पादन 8.157 करोड़ टन (अस्थायी) तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2024 के 7.871 करोड़ टन से अधिक है। इस बीच, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का कोयला उत्पादन अप्रैल में करीब 6.21 करोड़ टन रहा, जो घरेलू कोयला उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक है। अप्रैल 2024 में सीआईएल का कोयला उत्पादन 6.18 करोड़ टन रहा था। सीआईएन ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समूचे वित्त वर्ष 2024–25

में कोयला उत्पादन 78.11 करोड़ टन रहा था। यह वित्त वर्ष के लिए कंपनी के 83.8 करोड़ टन के लक्ष्य से करीब सात प्रतिशत कम रहा। कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025–26 के 87.5 करोड़ टन के उत्पादन और 90 करोड़ टन के उठाव का लक्ष्य रखा है।

सम्पादकीय

सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अमृतकाल

वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ देश में सकारात्मक परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो कार्य प्रारंभ हुआ, उसे जारी रहते हुए 11 वर्ष हो गए। ये 11 वर्ष भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की न केवल नींव बने, बल्कि भारत की संस्कृति को जीवंतता भी प्राप्त हुई। इस सबका केंद्र बिंदु है भारतीय संस्कृति और विरासत को सहेजने एवं संवारने के प्रति प्रधानमंत्री का समर्पण। उनके कार्यकाल में हमारी महान धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार कर उसे पुरानी गरिमा वापस दिलाने का भगीरथ प्रयास हुआ है। 'विरासत भी, विकास भी' जैसे दृष्टिकोण के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ध्वजा फहरा रही है। मैं अक्सर चिंतन करता था कि अहिल्याबाई होलकर की तरह क्या कोई हमारी महान सांस्कृतिक चेतना को फिर से प्रतिष्ठित करने में सहायक होगा? रामलला का अपने घर विराजमान होना, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं महाकाल लोक कारिडोर का निर्माण, सोमनाथ मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार, करतारपुर साहिब कारिडोर तैयार होना, चार धाम परियोजना का विकास, बुद्ध एवं जैन सर्किट के निर्माण के जरिए मोदी सरकार ने न केवल देश की सांस्कृतिक विरासत को एकसूत्र में पिरोया, बल्कि उसे अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ गर्व से खड़ा होना भी सिखाया। वर्षों बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ जम्मू–कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन हुआ। दशम गुरु गोबिंद सिंह के सुपुत्रों के बलिदान को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा भी बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक रही। हमारी विदेश नीति में भी देश के सांस्कृतिक महत्व को स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री विदेशी अतिथियों को श्रीमद्भगवद्गीता जी, तुलसी जी का पौधा या भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजें भेंट करते हैं। जी–20 शिखर सम्मेलन और उसके पहले इस समूह की देश भर में आयोजित बैठकों में हमने दुनिया को अपनी संस्कृति से परिचित कराया। वर्षों से देश से सैकड़ों प्राचीन की मूर्तियां और कलाकृतियां चोरी करके विदेश भेजी जाती रही हैं। हम ऐसे समाचार पढ़ते थे, लेकिन कभी मूर्तियों की वापसी की खबरें देखने–पढ़ने को नहीं मिलती थीं। 2014 के बाद यह भी बदलाव हुआ। अब चोरी और लूट के जरिए विदेश पहुंचीं कलाकृतियों और मूर्तियों के लौटने की खबरें आने लगी हैं। 2014 के बाद से अब तक विदेश से लगभग 642 प्राचीन मूर्तियां और धरोहर वापस आई हैं। योग और आयुर्वेद को भी बीते 11 वर्षों में वैश्विक स्वीकृति मिली। कोरोना काल में वर्तमान पीढ़ी ने आयुर्वेद के महत्व को और अच्छे से समझा। इस बार 21 जून को हम 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यह विशेष गर्व की अनुभूति वाला क्षण है, क्योंकि योग दिवस को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रधानमंत्री की पहल से ही मिली। देश में गोवंश की महत्ता फिर से स्थापित हुई है। डिजिटल इंडिया अभियान के साथ सांस्कृतिक डाक्यूमेंटेशन का भी अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक डिजिटल डाटाबेस' के माध्यम से दो लाख से अधिक सांस्कृतिक संस्थाओं और विरासत स्थलों का डिजिटल रिकार्ड तैयार किया गया है। एक भारत–श्रेष्ठ भारत, काशी– तमिल संगमम, सौराष्ट्र–तमिल संगमम और विरासत का उत्सव जैसे अभियानों से सांस्कृतिक एकता मजबूत करने का प्रयास किया गया है। संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थलों के आधुनिकीकरण का भी प्रयास हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव संग्रहालय तैयार किया गया है। लगभग 500 से अधिक स्मारकों का संरक्षण किया गया है। प्रधानमंत्री ने विदेश में बसे भारतीय प्रवासियों को सांस्कृतिक राजदूत बनने की प्रेरणा दी और आह्वान किया कि वे भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाएं। विविधताओं के इन उत्सवों से राष्ट्रीयता का जो अमृत निकल रहा, वह भारत को अनंतकाल तक ऊर्जावान रखेगा। सनातन संस्कृति और उसकी आत्मा क्या है? अखंड भारत का विचार क्या है? भारत अनेकता में एकता का देश कैसे है और पूरा देश एक सूत्र में कैसे पिरोया हुआ है? इस सबका दर्शन हमें पूर्ण महाकुंभ में मिला। प्रयागराज में मुझे दिव्य ऊर्जा का जो आभास हुआ, उससे यह विश्वास हो गया कि इस देश की आध्यात्मिक चेतना को कोई डिगा नहीं सकता। यह ऐसा आयोजन था, जो यदि न हुआ होता तो दुनिया नहीं मानती कि ऐसा आयोजन हो भी सकता है। आपरेशन सिंदूर की भी चर्चा आवश्यक है। हमारी पराक्रमी सेनाओं ने आतंकवाद को जैसा करारा जवाब दिया, उसने दुनिया में भारत की नई पहचान को प्रतिष्ठित किया। न्याय की अखंड प्रतिज्ञा के विचार तले आपरेशन सिंदूर के महानायकों को नमन। बीते 11 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत मंडपम और नया संसद भवन बनते देखा। संसद में सेंगोल स्थापित होते और जलियांवाला बाग का पुनरुद्धार होते भी देखा। हमने डिफेंस कारिडोर बनते देखा तो चिनाब पर सबसे ऊंचा रेल पुल भी। हम 'मेक इन इंडिया' के साथ 'मेड इन इंडिया' के साक्षी भी बने।

पाकिस्तानी जासूसों का मकड़जाल, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और सर्विलांस का हो उपयोग

पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से 26 निर्दोष भारतीयों की उनका मजहब पूछकर हत्या करने और आपरेशन सिंदूर के बाद से देश के अनेक हिस्सों से एनआइए सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, असम आदि राज्यों में करीब दो दर्जन पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए हैं। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सर्वाधिक चर्चित ज्योति मल्होत्रा है। वह एक ट्रैवल ब्लागर है। वह पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग गई थी। वह अन्य मौकों पर भी वहां जाती थी। वह कई बार पाकिस्तान गई और वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ से भी मिली। उसके साथ जसबीर सिंह को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह भी ब्लागर है। इनके अलावा कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें एक है रविंद्र मुरलीधर वर्मा, जो मुंबई में सुरक्षा ठेकेदार था। आरोप है कि उसने नौसेना के 14 जहाजों सहित सामरिक महत्व की कई जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलरों को दी। वर्मा अपने कार्यालय जाकर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मानचित्रों, सूचनाओं और अभिलेखों को किसी तरह अपने लैपटाप के जरिये आइआसआइ के एजेंटों को भेजता था। एक अन्य अमन यादव को भी एनआइए ने जासूसी के आरोप में गोरखपुर से गिरफ्तार किया है।

सीआरपीएफ के मोतीराम जाट को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। यूपी एटीएस ने रामपुर से जिस शहजाद को गिरफ्तार किया, उसका पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों से संबंध था। यही कहानी हरियाणा के तारीफ की है। वह पांच बार पाकिस्तान गया और फिर एक लाख रुपये के लालच में उसने सेना के ठिकानों की जानकारी पाकिस्तानी उच्चायोग के उस अधिकारी को दी, जो उसे और उसके दोस्तों को पाकिस्तान का वीजा दिलाता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में अजनाला के दो ऐसे लोग भी हैं, जो पहले दलित थे और फिर ईसाई बन गए थे। यह इसलिए हैरान करता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ईसाइयों पर बहुत अत्याचार होते हैं। नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह ढिल्लन, मुर्तजा अली, सुखप्रीत, करनबीर, यासीन, गजाला खातून, सूरज मसीह जैसे अन्य लोग भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं।

यह सिलसिला अब भी कायम है। ट्रैवल ब्लागर से लेकर सुरक्षा गार्ड, एप डेवलपर, आम नागरिक तक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं, जो हनी ट्रैप या पैसे के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ को लीक कर रहे थे। महाराष्ट्र में 65 साल के साकिब ने तो हद ही कर दी। 1993 के मुंबई एवं अन्य बम विस्फोटों में वह पोटा और टाडा में दस–दस साल की सजा काट चुका है। वह अफगानिस्तान जाकर अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर रूसी सेना से युद्ध भी कर चुका है। 2023 में जब एनआइए ने उसके यहां छापा मारा, तो उसके घर से आइएसआइएस के झंडे, एक–47, तलवार और जिहादी सामग्रियां मिलीं। वह आइएसआइएस की सदस्यता और समर्थन की शपथ भी ले चुका था। उसने अपने गांव पगड़ागांव का नाम बदलकर अलशाम रख लिया था और उसे सीरिया की तरह स्वतंत्र क्षेत्र बनाना चाहता था।

मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है आतंकवाद

कोई भी धार्मिक, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद की कोख से क्रांति नहीं, बल्कि सिर्फ घृणा, बर्बादी और हताशा जन्म लेते हैं। एक सच्चा और मानवीय उद्देश्य कभी भी खून–खराबे और हिंसा के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे सामने जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां आईं, वे समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन आतंकवाद एक ऐसी महामारी है जो अपने आप खत्म नहीं होगी। इसके खात्मे के लिए ठोस और सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, यह समाज, विकास और संसाधनों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का भारत दशकों से शिकार रहा है। हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें बेगुनाह पर्यटकों को केवल उनके धर्म के आधार पर मारा गया। यह क्रूरता और बर्बरता की पराकाष्ठा थी।

उमेश चर्तुवेदी

आज आतंकवाद पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। यह मानवता, शांति, सह–अस्तित्व, विकास और लोकतंत्र जैसे मूल्यों का शत्रु है। आतंकवाद एक ऐसी कट्टर सोच का परिणाम है जो सिर्फ विनाश, भय और नफरत को जन्म देती है। यह न तो कोई समाधान है, न ही किसी बदलाव का माध्यम बन सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आतंकवाद ने कभी कोई स्थायी या सार्थक परिणाम नहीं दिया है। आतंकवाद सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए विध्वंसक आडम्बर मात्र है यह सोचना भी एक भ्रम है कि कोई आतंकवादी किसी का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। कोई भी धार्मिक, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद की कोख से क्रांति नहीं, बल्कि सिर्फ घृणा, बर्बादी और हताशा जन्म लेते हैं। एक सच्चा और मानवीय उद्देश्य कभी भी खून–खराबे और हिंसा के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे सामने जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां आईं, वे समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन आतंकवाद एक ऐसी महामारी है जो अपने आप खत्म नहीं होगी। इसके खात्मे के लिए ठोस और सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, यह समाज, विकास और संसाधनों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का भारत दशकों से शिकार रहा है। हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें बेगुनाह पर्यटकों को केवल उनके धर्म के आधार पर मारा गया। यह क्रूरता और बर्बरता की पराकाष्ठा थी। इस हमले का मकसद भारत की एकता को तोड़ना और देश में डर फैलाना था, लेकिन ऐसी कोशिशें हमेशा असफल ही साबित होती हैं। यह सच है कि कोई भी मजहब निर्दोषों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। आतंकवादी केवल धर्म का नाम लेकर अपने कुकर्मों को वैधता देने की कोशिश करते हैं। अब हमारी नीति है कि आतंकवादी जहाँ भी हैं हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड के बीच अंतर किए बिना मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत अब पहले की तरह केवल प्रतिक्रिया करने वाला देश नहीं रहा। हमारी नीति में मौलिक परिवर्तन आया है। अब हम आतंकवाद के खिलाफ श्जीरो टॉलरेंसश नीति पर चलते हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 का ऑपरेशन सिंदूरकृये सभी कदम इस नई नीति का प्रमाण हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह आतंकवादी जहां भी होंगे, उन्हें खत्म करने से पीछे नहीं हटेगा। अब हम यह भेद भी नहीं करते कि आतंकवादी राज्य प्रायोजित हैं या किसी संगठन से जुड़े हैं। जो देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं, उन्हें भी अब सीधा जवाब दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ष्हम एक अकेले हमले को भी कई हमलों के समान मानते हैं। एक जनहानि भी अनेक जनहानियों के बराबर है। जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाता, भारत शांत नहीं बैठेगा।ष इस वक्तव्य के माध्यम से भारत की नीति की गंभीरता और दृढ़ता एक बार फिर सामने आई है।

ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने न केवल आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारतीय सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, आतंकवादियों का सफाया और उनके शिविरों को नष्ट करना एक आवश्यक कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा, जो इन्हें आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक समर्थन प्रदान करता है। जब तक उस संरचना को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक यह समस्या लौट–लौट कर सामने आती रहेगी। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन राष्ट्रों का भी खुलासा किया है जो आतंकवाद को रणनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा, तब तक उसे आर्थिक या कूटनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय पाकिस्तान को आर्थिक रूप से भी आघात पहुंचाने वाला है, क्योंकि सिंधु नदी प्रणाली उसकी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संकट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार, हाल के वर्षों में आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित देशों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह एक ऐसा वायरस है जो न सीमाओं की परवाह करता है और न ही धर्म, भाषा या संस्कृति की। यह पूरे विश्व की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे में, समय की मांग है कि वैश्विक समुदाय सभी प्रकार के मतभेदों और राजनीतिक स्वार्थों को एक ओर रख कर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करे। कोई भी रणनीतिक गठबंधन या राजनीतिक झुकाव इस वैश्विक लड़ाई की दिशा और प्रभाव को कमजोर नहीं करना चाहिए। इस लड़ाई में पहला और सबसे बुनियादी कदम आतंकवाद की एक सर्वस्वीकृत और व्यावहारिक परिभाषा तय करना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन' के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किया है, किंतु अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। इस स्पष्ट परिभाषा के अभाव में आतंकवादी हमलों की जांच, कानूनी कार्रवाई और अभियुक्तों के प्रत्यर्पण जैसी प्रक्रियाएं बाधित होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वैश्विक समुदाय शीघ्र एक स्पष्ट परिभाषा तय करे ताकि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई प्रभावी और न्यायपूर्ण हो सके। दूसरा, केवल आतंकी संगठनों को निशाना बनाना पर्याप्त नहीं है। उन देशों की आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित करना होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। पाकिस्तान इसका स्पष्ट उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को यह समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेलआउट पैकेज और ऋण किस प्रकार सीमापार आतंकवाद के पोषण में खर्च होते हैं। भारत ने प्डथ में दिए गए बयान में यह उजागर किया है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश को बार–बार आर्थिक सहायता देना न केवल गलत संदेश देता है, बल्कि वैश्विक मूल्यों की अवहेलना भी करता है। यह न केवल वित्तीय एजेंसियों की साख पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है, बल्कि ऐसे देशों के लिए एक तरह का प्रोत्साहन भी बन जाता है। जब तक पाकिस्तान अपने आतंकी नेटवर्क को पूर्णतः और ईमानदारी से समाप्त नहीं करता, तब तक उसे किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए। थ्।ज्थ् द्वारा उसे ग्रे लिस्ट में बनाए रखना एक तार्किक और अनिवार्य कदम है। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात यह तथ्य और स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में स्टेट और नान–स्टेट ऐक्टर्स की गतिविधियों में कोई विभाजन रेखा नहीं बची है।

यह तथ्य तब और भी पुष्ट होता है जब लश्कर–ए–तैयबा (स्मज) और जैश–ए–मोहम्मद (श्रमड) जैसे संगठनों के आतंकवादियों को राज्य के अधिकारियों द्वारा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाता है। एक ऐसा देश, जिसके सैन्य अधिकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकियों की अंत्येष्टि में भाग लेते हों, उससे आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग की अपेक्षा करना भोलापन होगा। इसके अतिरिक्त, यह खतरा भी लगातार बना हुआ है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और वे नान–स्टेट ऐक्टर्स के हाथों में पहुंच सकते हैं। यह समस्त मानवता के लिए अत्यंत गंभीर खतरा है। अतः यह आवश्यक है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। चौथा, प्रॉक्सी युद्ध की चुनौती भी उतनी ही खतरनाक है। कुछ देश अपने मित्र राष्ट्रों की आड़ में अपने पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाते हैं, और जब तक इस प्रवृत्ति को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। आतंकी हमलों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया किसी विशेष स्थान या पीड़ितों की राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जब देश अपने हितों के अनुसार यह तय करते हैं कि किस हमले की निंदा करनी है और किसे अनदेखा करना है, तब यह आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों को कमजोर करता है और अप्रत्यक्ष रूप से आतंकियों को वैधता प्रदान करता है। पांचवां, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों के सुरक्षित ठिकानों का प्रभाव केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनोटेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी और स्वचालित प्रणालियों जैसी तकनीकों के प्रयोग ने इन संगठनों की पहुंच को वैश्विक स्तर पर विस्तृत कर दिया है। अब ये खतरे किसी एक भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं रहते। ऐसे में इनसे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग अनिवार्य है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 9ध्11 हमलों के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि हमें आतंकवाद के लिए किसी भी वैचारिक, राजनीतिक या धार्मिक औचित्य को दृढ़ता से अस्वीकार करना होगा। उन्होंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा था कि अब प्रत्येक देश की सुरक्षा की चिंता में पूरे विश्व के कल्याण की भावना भी समाहित होनी चाहिए। यही सोच हमें एकजुट कर सकती है। भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों को जड़ से समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है। हम विश्व के सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों से आह्वान करते हैं कि वे अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस संघर्ष में साथ आएं। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, शांत और स्थिर विश्व की रचना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

महाभियोग लाने के लिए सत्ता पक्ष को क्यों विवश किया जा रहा है?

मुख्य न्यायाधीश गवई ने भी कहा है कि 'वर्तमान कोलेजियम प्रणाली आलोचना से रहित नहीं है, पर इसका समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं हो सकता।' न्यायिक स्वतंत्रता की बात ठीक है, संवैधानिक है, पर न्यायपालिका सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं द्वारा मर्यादा पालन जरूरी है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचरण के प्रश्न लगातार उठते रहे हैं। न्यायमूर्तियों के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई जटिल है। संविधान के अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर कार्रवाई के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

हृदय नारायण दीक्षित

भारतीय न्यायपालिका विश्वास के संकट से गुजर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की घटनाओं से जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे पूरी न्याय प्रणाली में विश्वास कम हो सकता है।' यह गंभीर बात उन्होंने तब कही है, जब भ्रष्टाचार के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग पर सत्ता पक्ष विपक्षी दलों से विचार विमर्श कर रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने बीते दिनों कहा था कि 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सरकार न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के महाभियोग प्रस्ताव पर सभी दलों का सहयोग चाहती है।' उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने भी वर्मा को दोषी ठहराया है। देश में न्यायिक सुधारों की मांग काफी पुरानी है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। न्यायिक सुधारों की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था, पर जजों की नियुक्ति की उस प्रणाली को न्यायपालिका द्वारा निरस्त कर दिया गया था। कहा गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारिक लक्षण है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने भी कहा है कि 'वर्तमान कोलेजियम प्रणाली आलोचना से रहित नहीं है, पर इसका समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं हो सकता।' न्यायिक स्वतंत्रता की बात ठीक है, संवैधानिक है, पर न्यायपालिका सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं द्वारा मर्यादा पालन जरूरी है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचरण के प्रश्न लगातार उठते रहे हैं। न्यायमूर्तियों के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई जटिल है। संविधान के अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर कार्रवाई के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदन के सदस्यों का सामान्य बहुमत और वोट डालने वाले उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत अनिवार्य है। इसके पूर्व लोकसभाध्यक्षध्सभापति एक जांच समिति गठित करते हैं। इस जांच के बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है। न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में लोकसभा में पहला महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अपेक्षित बहुमत के अभाव में गिर गया। 2011 में कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने राज्यसभा द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर त्यागपत्र दे दिया था। 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश जे. पारदीवाला के विरुद्ध आरक्षण संबंधी आपत्तिजनक बयान पर महाभियोग का नोटिस दिया था। उसी साल लगभग 50 राज्यसभा सदस्यों ने न्यायमूर्ति एसके गंगेले के विरुद्ध नोटिस दिया था। उन पर जिला जज के यौन उत्पीड़न का आरोप था। जजेज इंक्वायरी एक्ट (1968) के अधीन जांच कमेटी बनाई गई थी। प्रस्ताव पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। 2017 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के न्यायमूर्ति सीवी नागार्जुन रेड्डी के विरुद्ध भी राज्यसभा सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव रखा था। 2018 में विपक्षी दलों ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के विरुद्ध भी महाभियोग के प्रस्ताव का प्रयास किया था। सिक्किम हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पीडी दिनाकरन के विरुद्ध आए प्रस्ताव पर राज्यसभा के सभापति ने आरोप जांचने के लिए समिति गठित की थी। दिनाकरन ने इसी दौरान त्यागपत्र दे दिया। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के 75 वर्ष के भीतर महाभियोग के सिर्फ पांच प्रस्ताव सिद्ध करते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया बहुत जटिल है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए विशेष सुरक्षा कवच उपलब्ध कराए हैं। कायदे से न्यायपालिका को स्वयं अपने तंत्र के भीतर भ्रष्टाचार और लोक शिकायतों की जांच का कोई ढांचा विकसित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संविधान निर्माता स्वतंत्र न्यायपालिका एवं सबको न्याय की गारंटी चाहते थे। संविधान सभा में (छह जून, 1949) सी. दास ने कहा था, 'विश्वास है कि डा. आंबेडकर एवं सदन के अन्य विधि विद्वान ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसमें लोगों को न्याय मिले।' सभा में सुप्रीम कोर्ट के कार्य आवंटन पर बहस चल रही थी। दास ने कहा, 'मेरे मित्र ब्रिटिश प्रणाली के न्याय निर्वचन पर क्यों मुग्ध हैं? प्रस्तावित उपबंधों के अनुसार एक न्यायालय से दूसरे एवं अंत में सर्वोच्च न्यायालय में अपील जाएगी। ऐसी हालत में जनसाधारण को न्याय कैसे मिलेगा?' विधिवेत्ता अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा, 'इंग्लैंड धनी देश है। जनसंख्या चार करोड़ है। हमारी जनसंख्या 30 करोड़ है। यहां गारंटी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा।' न्याय सबकी अभिलाषा थी और है। सभा में एम. थीरुमल राव ने कहा, 'न्यायालयों का जाल बिछ गया है, लेकिन इन न्यायालयों में वही जा सकते हैं जो संपन्न हैं। संप्रति न्यायिक प्रक्रिया बहुत महंगी है। संपन्न के लिए सर्वसुलभ है और गरीबों के लिए महादुर्लभ है।

यह स्थिति उस देश की है, जहां हजारों वर्ष पहले भी सर्वसुलभ राजव्यवस्था एवं न्यायव्यवस्था थी। ऋग्वेद के रचनाकाल में 'ग्राम्यवादिन' न्याय की छोटी इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश को स्थपति बताया गया है। बुद्ध काल की न्याय व्यवस्था बहुत लोकप्रिय थी। चंद्रगुप्त मौर्य (320 ईस्वी) के कार्यकाल में ग्राम न्यायालय, जनपद न्यायालय एवं केंद्रीय न्यायालय थे। गुप्त काल (पांचवीं सदी) की प्रशंसा में चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है कि 'कानून सरल और उदार थे। अपराधों की गुह्यता के आधार पर दंड व्यवस्था है।' आखिरकार चूक कहां हो रही है? निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमों का अंबार है।

समझना होगा कि हम मशीनों पर गुस्सा नहीं कर सकते

'डिंग डॉन्ग'.. दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे' क्या ये आवाज और इस घोषणा से आप परिचित हैं? जी हां, ये आम तौर पर मेट्रो ट्रेन में सुनाई देती है। इस शनिवार को जब बेंगलुरु में 'ग्रीन लाइन' मेट्रो सर्विस के वाजरहल्ली स्टेशन पर मेट्रो रुकी तो बिल्कुल ऐसी ही घोषणा हुई। यात्रियों ने धैर्य से दरवाजे खुलने का इंतजार किया, क्योंकि ट्रेन के पूरी तरह से रुकने के कुछ सेकंड बाद सिस्टम दरवाजे खोलता है। लेकिन किसी अज्ञात तकनीकी खराबी के कारण मेट्रो के कुछ दरवाजे नहीं खुले। ट्रेन चल पड़ी, जैसे हर स्टॉप के बाद चलती है, बिना यह जाने कि पीछे के डिब्बों में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उतरने को बेताब यात्री स्तब्ध रह गए, उन्होंने वहीं किया, जिसमें वो अच्छे हैं– घबरा गए! इसके बाद कुछ यात्रियों ने दिमाग में खुराफाती विचारों के साथ चीखना शुरू कर दिया और भीड़ भी उनके पीछे हो चली। किसी ने नहीं सोचा कि ये तर्कसंगत है भी या नहीं। और बेंगलुरु भी कोई अलग नहीं था। घबराए यात्री तेजी से भाग कर मेट्रो पायलट (मेट्रो ट्रेन के चालक को पायलट कहा जाता है) के केबिन के पीछे वाले लेडीज कोच में पहुंचे और पायलट केबिन का दरवाजा पीटना शुरू किया, जैसे वो किसी ऐसे 'घोड़े बेचके सोने वाले' रूममेट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यह पता नहीं कि घर में आग लगी है। धक्कामुक्की और हंगामे से डरे पायलट ने सोचा कि कुछ भयंकर हुआ है और उसने ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रेन एक निर्जन से स्थान पर जाकर रुक गई। जैसे ही उसने सावधानी से अपने केबिन का गेट खोला, उसके सामने गुस्साए यात्री खड़े थे, जो इस बात का जवाब मांग रहे थे कि क्यों उन्हें पिछले स्टेशन पर नहीं उतरने दिया गया। इसके बाद कुछ मिनटों तक तीखी नोकझोंक हुई। और आप जानते हैं कि जब भीड़ एकत्रित होती है तो कोई एक व्यक्ति तर्कसंगत तरीके से बात नहीं कर सकता। पायलट ने यह समझाने की विफल कोशिश की कि उसे पीछे हुई समस्या के बारे में पता नहीं था और जब यात्री उसके केबिन के दरवाजे को पीटने लगे तो उसने ब्रेक लगाए। चूंकि वह ट्रेन को वापस पीछे नहीं ले जा सकता था, इसलिए पायलट ने सभी यात्रियों से अपने–अपने डिब्बों में लौटने के लिए कहा। पायलट ने यात्रा फिर शुरू की और अगले स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। वही आंदोलनरत यात्री तत्काल इकट्ठा हो गए, पायलट के केबिन की ओर भागे और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उससे गलती के लिए स्पष्टीकरण मांगने लगे। उनमें से कुछ पिछले स्टेशन पर वापसी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी कह रहे थे। लोको पायलट ने पूरा मामला स्टेशन कंट्रोलर को रिपोर्ट किया, जिसने आकर स्थिति संभाली और वापसी की यात्रा में यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने में यथासंभव सहायता की। भारत में अभी 17 शहरों में 17 मेट्रो रेल सिस्टम संचालित हो रहे हैं, जिनकी कुल परिचालन दूरी 939.18 किमी की है। 2025 के अंत तक 18वीं ऐसी सेवा की शुरुआत के साथ ही कुल परिचालन दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी, जिससे हमारा मेट्रो सिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे लंबा सिस्टम बन जाएगा। भारत में अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम का पहला प्रकार उपनगरीय रेल थी, जो 16 अप्रैल 1853 को तत्कालीन बॉम्बे (आज के मुम्बई) में बनी था।

कोई यह भी नहीं भूल सकता कि हमारे पास 1873 में कलकत्ता (आज के कोलकाता) में घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा भी थी। आवागमन के मामले में तब से अब तक भारत मशीन और तकनीकी की सहायता से बहुत आगे बढ़ चुका है। विदेशों में ऐसी तकनीकी गड़बड़ियां सामान्य हैं। हाल ही मैंने ऐसी ही एक खराबी न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टेशन पर देखी। वहां यात्रियों को जब ये बताया गया कि तकनीकी कारणों से एक सेवा कुछ घंटों के लिए अस्थायी रूप से बाधित रहेगी तो सभी यात्री शांति से स्टेशन के बाहर आ गए। फंडा यह है कि आप मशीनों पर नाराज नहीं हो सकते। तकनीकी और ऊर्जा पर चलने वाली मशीनों की दुनिया में गड़बड़ी तो होगी ही, भले ही बार–बार ना हो। हमें धैर्य विकसित करना होगा और सीखना होगा कि ऐसी स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। अन्यथा ये दुनिया हम पर हंसेगी।

खेती को उद्योग की तरह फायदेमंद बनाने की जरूरत

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान संगोष्ठी को संबोधित किया

बाराबंकी (संवाददाता)। खेती–किसानी को भी अब उद्योगों की तरह विकसित कर फायदेमंद बनाने की जरूरत है। यह आह्वान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया। वह विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कुसुंभा गांव में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा की।उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का नतीजा बताया। कहा कि इसी के परिणाम स्वरूप 10 हजार से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक गांवों में जाकर किसानों से सीधे मिलकर खेती किसानी को उन्नतशील बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का लक्ष्य गांव के किसान और खलिहान हैं। कहा कि सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने पर है। आय तभी बढ़ेगी जब खेती में नवाचार किए जाएंगे। बताया कि हमारे यहां यूपी में एक हेक्टेयर में धान का औसत उत्पादन 30 क्विंटल है, जबकि कुछ स्थानों पर 100 क्विंटल है। हरियाणा व पंजाब में यूपी से दोगुना उत्पादन है। पश्चिम में भी डेढ़ गुना है। यह उत्पादन जब सभी जगह एक समान होगा, तभी आमदनी बढ़ेगी।खेती–किसानी हमारी संस्कृतिप्रमुख सचिव ने कहा कि एग्रीकल्चर को हमारा कल्चर (संस्कृति) कहा जाता है। लेकिन चिंता का विषय है कि किसानों की नई पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा और लाभ कम होता है। मेहनत कम और लाभ बढ़ाने के लिए ही सरकार इस तरह के आयोजन करा रही है। उन्होंने परंपरागत धान व गेहूं के साथ फल, सब्जी और फूलों की खेती करने अपील भी किसानों से की। कहा कि खेत समतल होगा तो कम खाद और पानी में फसल ज्यादा पैदा होगी। इस मौके पर उन्होंने किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड और विभिन्न अनुदान के लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप चाभियां भेंट की। उन्होंने आंबेडकर मैदान में पौधा भी रोपा।ग्रीन नेट हाउस बनाने की अपील उन्होंने ग्रीन नेट हाउस बनाकर पर्यावरण को फसल के अनुकूल बनाने वाले किसानों से सीख लेने की भी अपील की। कहा कि इस तरह के किसान ग्रीन नेट हाउस में फल, फूल व सब्जियां पैदा कर खेती को उद्योग की तरह कर रहे हैं।

बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

बाराबंकी (संवाददाता)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रण विजय सिंह ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त रमेश मास्टर को दोषी माना है।

कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बदोसराय थानांतर्गत एक गांव की वादिनी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी दो पुत्रियां पीड़िता (8) व उसकी बहन (6) गांव के ही रमेश मास्टर के घर 5 अप्रैल 2023 को 11 बजे पढ़ने गई थी। छोटी बेटी घर वापस आ गई लेकिन पीड़िता काफी देर से घर लौट कर आई और चारपाई पर लेट गई ।कुछ देर के बाद वह दर्द से कराहने लगी। पूछने पर उसने बताया छुट्टी के बाद रमेश मास्टर ने सभी को भेजने के बाद मुंह दबा कर मेरे साथ गलत काम किया।

तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर एक आठ साल की बच्ची की मौत, दो घायल

बाराबंकी (संवाददाता)। बाराबंकी के टिकैतनगर थाना क्षेत्र में हुए एक हादसे में आठ वर्षीय बच्ची की दुर्घटना में मौत हो गई। वह अपनी दो सहेलियों के साथ टहलने के लिए निकली थी।बाराबंकी जिले के टिकैतनगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह टहलने निकली तीन बच्चियों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दो अन्य को सीएचसी भेजा गया। दुर्घटना कर भाग रहे वाहन को पुलिस ने पीछा कर 12 किलोमीटर दूर बदोसराय से पकड़ा लेकिन चालक फरार हो गया। पुलिस ने वाहन मालिक को हिरासत में ले लिया है। घटना बुधवार सुबह 5रू30 बजे की है। टिकैतनगर कस्बे के मोहल्ला सरावगी के निवासी राधे कनौजिया की पुत्री पलक (8 वर्ष) अपनी दो सहेलियां राजू की पुत्री रानी (8 वर्ष) और धनीराम की बेटी शिवांशी (9 वर्ष) के साथ टहलने के लिए निकली थी।स्थानीय लोगों ने बताया कि टिकैतनगर दरियाबाद मार्ग पर कोतवाली के सामने बने भगत सिंह पार्क में खेलने के बाद बच्चियां निकली और सड़क पर टिकैतनगर थाने के पास पहुंची ही थी कि पीछे की ओर से डीजे साउंड लादकर आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पलक को रौंद दिया। अन्य दोनों बच्चियां भी चपेट में आकर सड़क पर गिरकर तड़फने लगीं।घटना थाने के सामने हुई इसलिए पुलिस तत्काल अपने वाहन से तीनों बच्चियों को सीएचसी टिकैतनगर लेकर पहुंची।

माह के अंतिम दिन खूब तपी जेठ की दुपहरी

बाराबंकी (संवाददाता)। ज्येष्ठ माह के अंतिम दिन जेठ की दुपहरी खूब तपी। तेज धूप की वजह से गर्म इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी से लेकर पशु पक्षी तक बेहाल दिखे। जिसे जहां पर भी छांव दिखी वह दो पल के लिए वहीं पर बैठकर सुस्ताने लगा। तपिश व उमस के कारण लोग घरों और कार्यालयों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। मंगलवार को दिन का तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तपिश भरी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। रात का पारा भी चढ़ने की उम्मीद है। इससे उमस भी बढ़ेगी। तपिश व गर्मी के कारण पंखों व कूलर से भी गर्म हवा निकलने से वह बेअसर साबित हो रहे हैं। तपिश व उमस के कारण लोग घरों और कार्यालयों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए।

ईंट से सिर कूंचकर पत्नी की हत्या की, आरोपी हिरासत में

परसेंडी (सीतापुर) (संवाददाता)। तालगांव के दानियालपुर में युवक ने ईंट से सिर कूंचकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद ही उसको हिरासत में ले लिया।

उससे घटना के कारणों की पूछताछ की जा रही है।इलाके के दानियालपुर गांव निवासी मैहरजहां (40) का खून से लथपथ शव मंगलवार दोपहर घर के अंदर खटिया पर पड़ा मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार किसी विवाद के बाद शाहिद ने ईंट से सिर कूंचकर पत्नी मैहरजहां की हत्या कर दी। मैहरजहां के माथे पर घाव का निशान भी देखा गया।आरोपी ने ऐसा क्यों किया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शाहिद की मां का कहना है कि वह गांव में ही अपने अन्य पुत्रों के घर में रहती हैं। घटना से पहले वह घर आई थीं। मैहरजहां भी खटिया पर बैठी थीं। वह बकरी भगाने के लिए बाहर तक गईं तब तक शाहिद ने मैहर का सिर कूंच दिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम पहुंच गई। टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए। मैहरजहां का मायका मानपुर के बखरिया में है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद ही उसको हिरासत में ले लिया।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ ट्रक चोरी का केस

सीतापुर (संवाददाता)। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी जय सिंह यादव का ट्रक 14 अक्तूबर 2020 को चोरी हो गया था। पीड़ित के मुताबिक वह उस दिन बीमार थे। इस वजह से आईटीआई रेलवे क्रॉसिंग खैराबाद के आगे बाग के पास ट्रक खड़ा करवा दिया था।

उसी रात चोरों ने ट्रक पार कर लिया। काफी तलाशने के बाद भी ट्रक नहीं मिला। खैराबाद पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी सूचना एआरटीओ को भी दी।

बताया कि वह तबसे केस दर्ज करवाने के लिए चक्कर लगा रहे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इस वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पांच साल बाद सोमवार को केस दर्ज कर लिया। काफी तलाशने के बाद भी ट्रक नहीं मिला। खैराबाद पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी सूचना एआरटीओ को भी दी।

वर्षों से नलकूप खराब, कैसे करें सिंचाई

कुछ नलकूप तो देखरेख के अभाव में बदहाल हो गए हैं, कई नलकूपों के भवन झाड़ियों से घिर गए

सीतापुर (संवाददाता)। राजकीय नलकूपों से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोई नलकूप आठ तो कोई पांच साल से खराब पड़ा है। कुछ नलकूप तो देखरेख के अभाव में बदहाल हो गए हैं। कई नलकूपों के भवन झाड़ियों से घिर गए हैं। ऐसे में किसान खेत की सिंचाई निजी व किराये के संसाधनों से करने के लिए मजबूर हैं।महंगी सिंचाई करने से खेती–बाड़ी का खर्च बढ़ जा रहा है। कई बार तो नुकसान तक उठाना पड़ता है। किसानों के मुताबिक शिकायत करने पर भी संबंधित विभाग के अधिकारी सुनते नहीं हैं। नलकूप भवन पर अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक के सीयूजी नंबर अंकित हैं लेकिन नंबर मिलाने पर कॉल रिसीव ही नहीं की जाती है।किसानों का कहना है कि सरकारी नलकूप सही करा दिया जाएं तो कम खर्च में अच्छी पैदावार होने से लाभ बढ़ जाएगा। कई बार अधिकारियों से शिकायत की लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।किसान शत्रुघन व देवकी नंदन ने बताया कि राजकीय नलकूप सिर्फ शोपीस बने हुए हैं। ऐसे में खेती करना मुश्किल हो गया है। किसान ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रावण सिंह व भगौती प्रसाद ने बताया कि नलकूप खराब होने से खेत में पानी काफी दूरी से लाना पड़ता है। इसमें 200 रुपये प्रति बीघा किराया देना पड़ता है। पाइप का किराया अलग से देना पड़ता है। पुत्तू लाल व सरजू ने बताया कि खेती करने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। यहां खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। सीयूजी नंबर मिलाते रहो, नहीं उठती कॉल नलकूप विभाग के अधिकारियों की मनमानी शासन के निर्देशों पर भारी है। राजकीय नलकूपों पर जेई, एई और ईई का सीयूजी नंबर इस उद्देश्य से अंकित कराया जाता है ताकि किसान अपनी समस्या अथवा शिकायत दर्ज करा सकें। मछरेहटा क्षेत्र के नलकूपों पर जेई का 9454414248, एई का 9454415780 और ईई का 9454414250 सीयूजी नंबर अंकित है। अलग–अलग नंबरों से तीनों सीयूजी नंबरों को कई बार मिलाया गया लेकिन न कॉल रिसीव हुई और न बैक कॉल ही आई।लीडआठ साल से सिंचाई का संकट, बोरिंग के गड्ढे से हादसे का भी खतरा कुनेहटा लच्छी रामपुर के मजरा रामुवापुर में नलकूप संख्या–174 लगभग आठ वर्षों से खराब है। यहां ट्रांसफार्मर व बिजली का कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है। पाइप निकाले जा चुके हैं। किसान प्रेम कुमार ने बताया कि नलकूप खराब होने से सिंचाई का तो संकट बना ही हुआ है, भवन भी खुला पड़ा है।

भीषण गर्मी में जाम में फंसे लोग

बाराबंकी (संवाददाता)। देवा रोड पर ओवरब्रिज के पास बने एक गड्ढे में फंसकर मिक्सर प्लांट का पहिया टूट गया। इसके चलते मंगलवार सुबह इस रूट पर भीषण जाम लग गया। सुबह नौ बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक चले जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे जाम में फंसे वाहनों में सवार बच्चों से लेकर बड़ों तक को भीषण गर्मी में काफी परेशानी उठाना पड़ी। जाम के कारण मरीजों को भी समय से अस्पताल पहुंचने के लिए जूझना पड़ा। कोई वैकल्पिक मार्ग न होने से ट्रैफिक को डायवर्ट किए बिना ही काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने गड्ढे में फंसे मिक्सर प्लांट को हटवाया। इसके बाद ही इस रूट पर ट्रैफिक संचालक पूरी तरह बहाल हो सका। देवा मार्ग पर एफसीआई गोदाम के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग के समीप सड़क पर काफी गहरे गड्ढे बने हैं।

ट्रक में पीछे से भिड़ी लखनऊ आ रही बस

बाराबंकी (संवाददाता)। लखनऊ–अयोध्या मार्ग पर सुबह परिवहन निगम की जनरथ बस गंगरेला गांव के निकट आगे जा रहे ट्रक में पीछे से भिड़ गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 24 यात्री घायल हो गए। इनमें से तीन यात्रियों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बस गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी। इस दौरान गंगरेला गांव जिले की सीमा पर स्थित अयोध्या जिले के पटरंगा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। सभी घायलों को रामसनेहीघाट सीएचसी पहुंचाया गया। जहां से बाकी का इलाज कर नौ घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया।

उमस भरी गर्मी में बिजली संकट से लोग परेशान, शहर में भी करवटों में गुजर रही रात

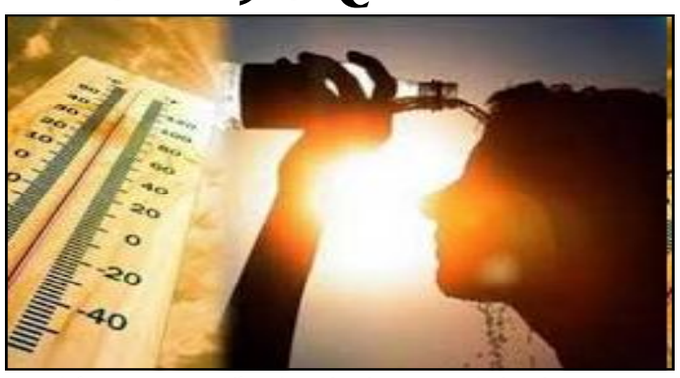

हरदोई (संवाददाता)। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली कटौती बढ़ गई है। शहर भर में बिजली संकट से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक ओर विद्युतीकरण पर लाखों खर्च कर दिए गए और थोड़ा सा ओवरलोड होते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। सुबह से रात और दिन में बिजली संकट के कारण लोगों की रात करवटों में गुजर रही है। साथ ही कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। जिले में विद्युतीकरण पर भले ही भारी भरकम बजट खपाया गया हो, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। गर्मी में इजाफा होते ही बेतहाशा बिजली कटौती हो रही है। ओवरलोडिंग के कारण फीडरों पर ट्रिपिंग 200 गुना बढ़ गई है। हर 15 से 20 मिनट पर बिजली की आवाजाही लगी रहती है। इससे लोगों को गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। सोमवार रात को भी सांडी रोड उपकेंद्र के अंतर्गत रामदत्त चौराहे से बावन चुंगी के बीच रात भर लाइट की आवाजाही लगी रही। इस कारण से लोग सही ढंग से सो भी नहीं पाए।उधर, आवास विकास कॉलोनी के सी ब्लॉक में ओवरलोडिंग की वजह से बिजली के खंभे में आग लग गई। इस कारण से लोग सही ढंग से सो भी नहीं पाए।उधर, आवास विकास कॉलोनी के सी ब्लॉक में ओवरलोडिंग की वजह से बिजली के खंभे में आग लग गई। इस कारण से दिन में करीब दो घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।शहर के अन्य मोहल्लों में भी आपूर्ति प्रभावित होने की सूचना मिलती रही। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी में काफी परेशान होना पड़ा। अधिशासी अभियंता सूर्य कुमार ने बताया कि लोड बराबर करने के लिए बार–बार ट्रिपिंग की जा रही है। विद्युत व्यवस्था बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही। एक ओर विद्युतीकरण पर लाखों खर्च कर दिए गए और थोड़ा सा ओवरलोड होते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। सुबह से रात और दिन में बिजली संकट के कारण लोगों की रात करवटों में गुजर रही है। साथ ही कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। जिले में ओवरलोडिंग के कारण फीडरों पर ट्रिपिंग 200 गुना बढ़ गई है। हर 15 से 20 मिनट पर बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।शहर के अन्य मोहल्लों में भी आपूर्ति प्रभावित होने की सूचना मिलती रही। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी में काफी परेशान होना पड़ रहा है। सोमवार रात को भी सांडी रोड उपकेंद्र के अंतर्गत रामदत्त चौराहे से बावन चुंगी के बीच रात भर लाइट की आवाजाही लगी रही। इस कारण से लोग सही ढंग से सो भी नहीं पाए।उधर, आवास विकास कॉलोनी के सी ब्लॉक में ओवरलोडिंग की वजह से बिजली के खंभे में आग लग गई।

अब फर्म संचालक और ठेकेदारों से होगी वसूली

हरदोई (संवाददाता)। क्षेत्र पंचायत भरावन में जीएसटी और लेबर कटौती न कर शासकीय क्षति पहुंचाई गई।मजदूरी के रुपये कार्य प्रभारियों के खातों में दिए जाने की गड़बड़ी के साथ ही जीएसटी और लेबर सेस की कटौती न किए जाने के लिए उस समय तैनात रहे लेखाकार और पांच बीडीओ दोषी पाए गए हैं। जिला लेखा परीक्षा विभाग ने भुगतान पाने वाली फर्म और ठेकेठारों से जीएसटी और लेबर सेस की वसूली की संस्तुति की है।क्षेत्र पंचायत भरावन में 15वें वित्त और राज्य वित्त आयोग की मद में साल 2021–22 में 25 कार्यों के लिए करीब एक करोड़, 32 लाख, 79 हजार, 929 रुपये का भुगतान किया गया। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी व लेबर सेस की कटौती न कर करीब तीन लाख, 83 हजार, 285 रुपये की शासकीय हानि की गई है। जिला लेखा परीक्षा विभाग ने ऑडिट के परिपालन के साथ ही जीएसटी और लेबर सेस की वसूली फर्म व ठेकेदारों से किए जाने की संस्तुति की है।

अस्पताल में लगे एसी-कूलर बने शोपीस, उमस से मरीज बेहाल

हरदोई (संवाददाता)। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की व्यवस्थाएं मरीजों को बीमार कर दे रही हैं। उपचार के लिए आए मरीजों को गर्मी और उमस से परेशान होना पड़ रहा है। ओपीडी समेत महिला चिकित्सालय में पर्चा बनवाने से दवा लेने तक मरीजों के पसीने छूट जा रहे हैं। गर्मी की वजह से मरीज और तीमारदारों का दम फूला जा रहा है।उमस भरी गर्मी में अस्पताल में इलाज कराना भारी पड़ रहा है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। आलम ये है कि अस्पताल में गर्मी से बचाव के लिए बेहतर व्यवस्था ही नहीं हैं। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना दो हजार से अधिक पर्चे बनते हैं। ओपीडी भवन के भूतल पर बने पर्चा और दवा काउंटर पर हर समय लोगों की भीड़ रहती है। ऐसे में वहां उमस इस कदर होती है कि अंदर घुसते ही शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है।इसके बाद भी वहां हवा का कोई बेहतर इंतजाम नहीं है। चार एसी लगे हैं, लेकिन दो ही काम कर रहे हैं। कूलर लगे हैं उनमें कभी पानी नहीं भरा जाता। दवा लेने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है। इसी प्रकार महिला चिकित्सालय में भी व्यवस्था बेहतर नहीं है।

ओपीडी में सभी कूलर काम नहीं कर रहे हैं और एसी भी नहीं हैं। मरीजों का गर्मी से हाल बेहाल है। पंखों से निकल रही गर्म हवा हरदोई। भीषण गर्मी में पंखे आग उगल रहे हैं। वार्ड में भर्ती मरीजों को उमस भरी गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिला अस्पताल की ओटी का एसी काम नहीं कर रहा और वार्ड में भी कूलर नहीं हैं।

लूटपाट करने वाले गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

बाराबंकी (संवाददाता)। किराये की कार में लंबी दूरी की सवारी बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट करने वाले शातिर गिरोह के पांच सदस्यों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस गिरोह ने दो दिन पहले सिद्धार्थ नगर के एक यात्री को लखनऊ से बैठाकर लूटने के बाद जिले के देवा कोतवाली क्षेत्र के माती के पास फेंक दिया था। स्वाट, सर्विलांस सेल तथा नगर कोतवाली और जहांगीराबाद थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र का निवासी शिवम यादव अभी फरार है। पकड़े गए लुटेरों में लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र निवासी सुमित वर्मा, नितिन यादव व सुदेश यादव तथा पीजीआई थाना क्षेत्र के अभिषेक ठाकुर और मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के निवासी हिमाचल चौहान शामिल हैं।

शादीशुदा बहन को परेशान करता था...नाराज भाई ने चाकू से गोदकर की हत्या- पहले मना भी किया

गोरखपुर (संवददाता)। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुजुरी खुर्द गांव के रहने वाले हरिप्रसाद गौंड के बेटा आदित्य उर्फ सूरज (22) की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। बहन से फोन पर बात करने से नाराज भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर एसओजी टीम और खुखुंदू पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू और अन्य सामग्री बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुजुरी खुर्द गांव के रहने वाले हरिप्रसाद गौंड का बेटा आदित्य उर्फ सूरज रविवार की रात करीब 10रू30 बजे भोजन करने के बाद घर से अकेले निकला था। सोमवार की सुबह सूचना मिली कि गांव के बाहर खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। जब परिवार के लोगों ने मौक पर पहुंचकर आदित्य उर्फ सूरज के रूप में उसकी पहचान की। किसी ने इसकी सूचना खुखुंदू थाने को दी मौके पर पहुंचे प्रभारी थानेदार लवकुश यादव ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी विक्रांत वीर के साथ मातहत भी मौके पर पहुंच गए। एसपी ने घटनास्थल पर मौजूद मृतक परिजनों से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस लाइंस में घटना का खुलासा करते हुए एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि मृतक के पिता के तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। विवेचना के क्रम में एसओजी प्रभारी दीपक कुमार और प्रभारी थानेदार लव कुश ने संदेह होने पर कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि कड़ाई से पूछताछ में नितेश गौड़ ने बताया कि उसकी बहन कि शादी हो चुकी है।

जेई ने मांगी अपनी गाड़ी- दोस्त ने धमकाया

गोरखपुर (संवददाता)। शाहपुर थाना क्षेत्र के पूर्वोत्तर रेलवे में जूनियर इंजीनियर संतोष श्रीवास्तव की स्कॉर्पियो उनके दोस्त ने हड़प ली है। कुछ दिन के लिए आरोपी दोस्त गाड़ी मांगकर ले गया था। आरोप है कि गाड़ी मांगने पर आरोपी ने धमकी दी। पुलिस ने आरोपी बांसगांव इलाके के वार्ड संख्या 12 दक्षिण टोला निवासी मनीष सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। शाहपुर इलाके के जंगल मातादीन स्थित नाथपुरम कॉलोनी निवासी संतोष कुमार श्रीवास्तव पूर्वोत्तर रेलवे में जूनियर इंजीनियर (जेई) पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने शाहपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 24 अगस्त 2023 को लोन पर स्कॉर्पियो कार खरीदी थी। कुछ दिन बाद बांसगांव निवासी उनके दोस्त मनीष सिंह गाड़ी मांगकर ले गए और कहा कि वह इसकी किस्त जमा करते रहेंगे। किस्त जमा नहीं करने पर गाड़ी मांगी तो वह टालमटोल करते हुए टरकाने लगा। इसी तरह करते हुए डेढ़ साल बीत गया। एक दिन फोन करने पर आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि भूल जाओ, न कार देंगे न ही किस्त जमा करेंगे।

हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड : मुख्य आरोपी कबूलनामा- मैने ही मारी थी गोली, इनकांउटर में हुआ घायल- चल रहा इलाज

गोरखपुर (संवददाता)। गोरखपुर पुलिस के अनुसार, उसने बताया कि वह अगर दिनेश को नहीं मारता, वह उसकी हत्या कर देता। छह डिसमिल जमीन व तालाब के पट्टे को उसने विवाद की जड़ बताया। पुलिस पूछताछ में मिलीं जानकारियों और अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह–जगह दबिश दे रही है। बेलीपार थाने के भरवलिया गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर दिनेश निषाद की हत्या का मुख्य आरोपी जुगुल निषाद का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सोमवार रात मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा था। मंगलवार शाम उसे जिला अस्पताल से बीआरडी रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक, जुगुल से पूछताछ में पता चला कि उसने ही अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दिनेश की गोली मारकर हत्या की थी। घटनास्थल पर पिस्टल इसलिए फेंकी, ताकि लगे कि दिनेश से बचने के लिए आत्मरक्षा में उसे गोली मारी गई है। पुलिस के अनुसार, उसने बताया कि वह अगर दिनेश को नहीं मारता, वह उसकी हत्या कर देता। छह डिसमिल जमीन व तालाब के पट्टे को उसने विवाद की जड़ बताया। पुलिस पूछताछ में मिलीं जानकारियों और अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह–जगह दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात जुगुल निषाद के बारे में पता चला कि वह जिला छोड़कर भागने की तैयारी में है। इसके बाद सीओ बांसगांव दरवेश कुमार व थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह टीम के साथ बांसगांव मुख्य मार्ग पर कुसमौल गांव के पास उसके आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच जुगुल बाइक से पहुंचा तो सीओ बांसगांव ने उसे रोकने की कोशिश की। इस पर जुगुल ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते उसके बाएं पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। इसके बाद इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जुगुल के पास से चार कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है। एसएसपी राजकरन नय्यर ने बताया कि जुगुल निषाद ने पूछताछ में खुद की सुरक्षा को लेकर दिनेश की हत्या करने की बात स्वीकार की है। पूछताछ में जुगुल ने बताया है कि हिस्ट्रीशीटर दिनेश से छह डिसमिल जमीन व तालाब के पट्टे को लेकर अदावत चल रही थी। दिनेश की हत्या के पीछे पहली वजह जुगुल से वर्षों से चले आ रहे जमीन का विवाद ही है। जहां तक तालाब के पट्टे की बात है, उसकी जांच कराई जा रही है। बेलीपार थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह ने बताया कि दिनेश की हत्या के बाद उसके भाई रमेश की तहरीर पर आठ नामजद समेत 11 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था।

लोवोल्टेज के कारण उपभोक्ता परेशान

सीतापुर (संवाददाता)। दो दिन से लोवोल्टेज के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने मंगलवार को पावर हाउस पर प्रदर्शन कर समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग की। इस पर जेई ने कहा कि पावर हाउस को फोन करो। ग्रामीणों ने बताया कि लाइनमैन अशोक कुमार किसी का फोन ही नहीं उठाते हैं। पावर हाउस का सीयूजी फोन कभी नहीं उठता है। पावर हाउस के कर्मचारी उपभोक्ताओं से बात नहीं करना चाहते हैं।

महदेइया बाजार के चौकी प्रभारी श्रवण चन्द्र ने बिना हेलमेट बाइक चालकों को नि:शुल्क हेलमेट पहनाकर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया।

उतरौला बलरामपुर माडर्न थाना श्रीदत्तगंज अन्तर्गत ग्राम महदेइया बाजार के चौकी प्रभारी श्रवण चन्द्र ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। क्षेत्र में बढ़ते वाहन से दुर्घटना को देखते हुए चौकी प्रभारी ने बिना हेलमेट के मोटर साइकिल चालकों को नि:शुल्क हेलमेट देकर उन्हें यातायात नियमों की सीख दी। थाना श्रीदत्तगंज के चौकी महदेइया बाजार के चौकी प्रभारी श्रवण चन्द्र ने बताया कि क्षेत्र में वाहनों से बढ़ रही दुर्घटना का मुख्यकारण वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का पालन न किया जाना और मोटर साइकिल वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट न लगाएं जाने से सिर में गम्भीर चोट के लगने से मौत तक हो जाती है। मोटर साइकि ल चालक को सीख देने के लिए यातायातनियमों की जानकारी दी जाती है,और उन्हें पुलिस की ओर से मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट लगाए जाने की सीख देते हुए नि:शुल्क हेल मेट वितरित किया गया है। चौकी प्रभारी के इस अनोखी पहल की प्रशसा पुरे क्षेत्र में की जा रही है।

श्रावस्ती महिलाओं के साथ किया जाए संवेदनशील व्यवहार-प्रियंका मौर्या

जिला संवाददाता श्रावस्ती रवि नन्दन शुक्ला की रिपोर्ट '

श्रावस्ती बेटियों को शिक्षित कर आगे बढ़ायें अभिभावक–प्रियंका मौर्या

प्रदेश के राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्या डा0 प्रियंका मौर्या जी जनपद में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने तथा महिला जनसुनवाई एवं समीक्षा किये जाने हेतु दो दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंची। तत्पश्चात् मा0 सदस्या जी ने विकास भवन सभागार पहुंचकर महिला उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान मा0 सदस्या को कुल 25 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 02 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा कुछ न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण थे। शेष अन्य शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस अवसर पर मा0 सदस्या ने महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं व शिकायतों से रूबरू होते हुए कहा कि समस्याओं से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित न्याय देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि महिलाओं के साथ सवेंदनशील व्यवहार किया जाए। इसी उद्देश्य से मैं यहां की महिलाओं को भी यही कहना चाहती हूं कि अपने जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ायें, जिससे उनका पारिवारिक जीवन सुखी ढंग से चल सके। उन्होने सभी अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि लड़का–लड़की में भेदभाव न करें, दोनों को समान शिक्षा दें, जिससे बेटियां भी अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन करें। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं शिक्षित कर उन्हें बराबरी का अधिकार दिलाना है।

उन्होने कहा कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि वे महिलाओं एवं बालिकाओं छोटी–बड़ी शिकायतों को गम्भीरता से लें और त्वरित कार्यवाही कर उन्हे न्याय शुलभ करायें ताकि समस्याओं से ग्रसित महिलाओं एवं बालिकाओं को न्याय के लिए इधर–उधर भटकना न पड़े और उनका मान–सम्मान प्रत्येक दशा में कायम रहे।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अमरेन्द्र कुमार वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा भरत पासवान, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 अमरनाथ यति महिला थाना प्रभारी सहित सम्बन्धित अधिकारीगण एवं पीड़ित महिलाएं उपस्थित रही।

जिलाधिकारी ने एन0आर0एल0एम0 कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

श्रावस्ती। 11 जून, 2025। सू0वि0। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कार्यालय जिला ग्रामीण अजीविका मिशन, श्रावस्ती का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद व डी0सी0 एन0आर0एल0एम0 राजीव कुमार उपस्थित रहे। बाल विकास पुष्टाहार विभाग को दी जाने वाले पोषाहार के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। ज्ञात हुआ कि टी0एच0आर0(टेक होम राशन) द्वारा आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने टी0एच0आर0 की आडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो संज्ञान में आया कि मई 2025 में प्राप्त हुई थी परन्तु डी0सी0 एन0आर0 एल0एम0 द्वारा उच्चाधिकारियों को आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई और न ही वार्ता किया गया। संज्ञान में आया कि टी0एच0आर0 प्लांट का जी0एस0टी0 पंजीकरण न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में उपस्थित

डी0सी0 एन0आर0एल0एम0 से पूछा गया कि बिना टिन जी0एस0टी0 कटौती के बावजूद भुगतान किया जा रहा है, उनके द्वारा बताया गया कि इसके सम्बन्ध में उन्हें कोई भी जानकारी नही है। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप द्वारा विभाग की संचालित योजनाओं में कोई भी रूचि नहीं ली जा रही है। यह अत्यन्त खेदजनक है।

निरीक्षण के दौरान यह भी संज्ञान आया है कि टेक होम राशन के लिए शासन द्वारा प्रेषित धनराशि व एस0एस0जी0 महिलाओं द्वारा एकत्रित धनराशि का वर्ष 2023 में उच्चाधिकारियों की अनुमति के बगैर बैंक में एफ0डी0 कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में डी0सी0 एन0आर0एल0एम0 से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह मेरे कार्यकाल का नहीं है और इस विषय में जानकारी नही है। इस पर जिलाधिकारी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आपका यह दायित्व है कि आपके विभाग में हो रही गतिविधियों को देखा जाए तथा अपने उच्चाधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जाए परन्तु आप द्वारा न ही योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और न ही पूर्ण मनोयोग से कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच करते हुए रिपार्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त सम्बन्धित दोषी अधिकारीध्कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का भागीदारी न्याय सम्मेलन 14 जून को, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी होंगे आयोजन

लखनऊ (संवाददाता)। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने विभिन्न जातियों को गोलबंद करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत अब जिलेवार भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न जिलों के साथ ही कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में भी यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 जून को लखनऊ से हो रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़ी जातियों पर फोकस किया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले। इसके बाद से लगातार सामाजिक न्याय और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग की जा रही है। पार्टी विभिन्न आयोजनों के जरिए आरक्षण की सीमा भी बढ़ाने की मांग कर रही है। अब भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 14 जून को होने वाले भागीदारी न्याय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयसिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भागीदारी न्याय सम्मेलन में 14 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत हर जिले में भागीदारी न्याय पदयात्रा, ओबीसी वर्ग के विभिन्न जातियों का जातीय सम्मेलन, एक जुलाई से 14 जुलाई तक विभिन्न यूनिवर्सिटी –कॉलेज के युवाओं में भागीदारी न्याय, शिक्षा एवं रोजगार के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वे, संस्थागत सर्वे कराने और आरक्षण की 50 फीसदी सीमा हटाने की मांग को लेकर गांव गांव चौपाल, बिजली निजीकरण की वजह से आरक्षित वर्ग की नौकरियों पर आए संकट आदि को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

बाघिन को बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद गोरखपुर प्राणि उद्यान बंद

लखनऊ (संवाददाता)। कानपुर प्राणि उद्यान के बाद गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान में भी बाघिन को एविएंजा फ्लू की पुष्टि हो गई है। इसके बाद गोरखपुर और कानपुर प्राणि उद्यान को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य जीव अनुराधा वेमुरी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर निरंतर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके पहले प्रदेश के कई जिलों के जू बीते दिनों बंद रहे थे। मानसून सीजन को देखते हुए प्रदेश के तीनों टाइगर रिजर्व 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएंगे। मुख्य वन संरक्षक व फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, वन संरक्षकध्फील्ड डायरेक्टर रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट और प्रभागीय वनाधिकारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की संस्तुति और मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों के आधार पर वर्षाकाल की संभावना देखते हुए पर्यटन सत्र 15 जून से बंद करने का निर्णय लिया गया है।

सस्ते सामान के लिए ना करें जिंदगी से खिलवाड़

वाराणसी राजेश सेठ

विशेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल की एक बैठक आज विशेश्वरगंज स्थित कैंप कार्यालय में प्रतीक गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित व्यापारियों की राय एवं पीड़ा को समझते हुए अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता ने बताया कि आज आम जनता का रुझान माल व ऑन–लाइन खरीदारी की ओर हो चला है कारण उनके विज्ञापन एवं सस्ती चीजे को प्रोवाइड कराना, ऐसा वह इसलिए करते कि जनता सस्ती चीजे (समानों) की तरफ आकर्षित है जबकि कटु सत्य है कि रुपए मे तीन अठन्नी नहीं अपितु दो ही अठन्नी होती है यानी सस्ता सामान अगर कोई माल या ऑनलाइन ऑफर कर रही है तो निश्चित तौर उसकी क्वालिटी नकली या दोयम दर्जे की होगी अभी बीते दिनों एक प्रमुख ऑन लाइन विक्रेता के यहां मिल रही शिकायत पर छापेमारी की गई तो नकली यानी दोयम दर्जे की सामान बरामद हुई जो समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही है इसके बावजूद ऑन लाइन व माल द्वारा बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई जो यह दर्शाता है कि हमें क्वालिटी नहीं सस्ता सामान चाहिए वह भले ही घटिया हो चिंता का विषय है, घटिया सामानों के इस्तेमाल से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है हम रोगी वन अस्पतालों का चक्कर काट रहे हैं तथा अपनी कमाई का बड़ा भाग दवा पर खर्च कर रहे हैं।

उन्होंने जनता से अपील की कि जो भी वस्तुएं इस्तेमाल करें सस्ता नहीं अच्छा इस्तेमाल करें सस्ते के चक्कर में अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें।

प्रतीक गुप्ता ने िप के अधिकारियों से से मांग की कि माल व ऑन लाइन जैसे बड़े व्यापारियों के यहां नियमित रूप से छापेमारी करें जिससे आम जनता लुटने से बचे।

बैठक में उपस्थित सर्वश्री अलखनाथ गोस्वामी संतोष जायसवाल शरद केसरी आलोक सेठ पंकज अग्रवाल राजेश गुप्ता खुर्शीद अख्तर सुनील चौरसिया मनोज कपूर अजय यादव राजकिशोर जी सुरेंद्र गुप्ता सूरज गुप्ता विनोद केसरी दुर्गादास गुप्ता गणेश सेठ कुलदीप गुप्ता पीयूष पांडे जितेंद्र जायसवाल आकाश जायसवाल दीपक चौरसिया अभिषेक

मा0 सदस्या, राज्य महिला आयोग की ने जनसुनवाई कर सुनी महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याएं

जनसुनवाई में प्राप्त हुए 25 शिकायतें, 02 का किया मौके पर निस्तारण
महिलाओं के साथ किया जाए संवेदनशील व्यवहार–प्रियंका मौर्या
बेटियों को शिक्षित कर आगे बढ़ायें अभिभावक–प्रियंका मौर्या

श्रावस्ती, 11 जून, 2025। सू0वि0। प्रदेश के राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्या डा0 प्रियंका मौर्या जी जनपद में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने तथा महिला जनसुनवाई एवं समीक्षा किये जाने हेतु दो दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंची। तत्पश्चात् मा0 सदस्या जी ने विकास भवन सभागार पहुंचकर महिला उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान मा0 सदस्या को कुल 25 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 02 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा कुछ न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण थे। शेष अन्य शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस अवसर पर मा0 सदस्या ने महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं व शिकायतों से रूबरू होते हुए कहा कि समस्याओं से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित न्याय देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि महिलाओं के साथ सवेंदनशील व्यवहार किया जाए। इसी उद्देश्य से मैं यहां की महिलाओं को भी यही कहना चाहती हूं कि अपने जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ायें, जिससे उनका पारिवारिक जीवन सुखी ढंग से चल सके। उन्होने सभी अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि लड़का–लड़की में भेदभाव न करें, दोनों को समान शिक्षा दें, जिससे बेटियां भी अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन करें। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं शिक्षित कर उन्हें बराबरी का अधिकार दिलाना है।

उन्होने कहा कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि वे महिलाओं एवं बालिकाओं छोटी–बड़ी शिकायतों को गम्भीरता से लें और त्वरित कार्यवाही कर उन्हे न्याय शुलभ करायें ताकि समस्याओं से ग्रसित महिलाओं एवं बालिकाओं को न्याय के लिए इधर–उधर भटकना न पड़े और उनका मान–सम्मान प्रत्येक दशा में कायम रहे।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अमरेन्द्र कुमार वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा भरत पासवान, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 अमरनाथ यति महिला थाना प्रभारी सहित सम्बन्धित अधिकारीगण एवं पीड़ित महिलाएं उपस्थित रही।

मा0 सदस्या, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में प्रेसवार्ता सम्पन्न

महिलाओं को समृद्ध एवं सशक्त बनाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदैव प्रयासरत–मा0 सदस्या, प्रियंका

श्रावस्ती। 11 जून, 2025। सू0वि0। प्रदेश के राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्या डा0 प्रियंका मौर्या जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता सम्पन्न हुई। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होने पत्रकार बन्धुओं से अपने अनुभव आदि के बारे में चर्चा की। उन्होने कहा कि आज उनके द्वारा जनसुनवाई की गई जिसमें उन्हें कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें से 02 का मौके पर निस्तारण किया गया। अधिकतर मामले महिलाओं के घरेलू हिंसा से सम्बन्धित रहे है। जिस पर उनके द्वारा महिलाओं एवं पुरूषों को बुलाकर दोनों पक्षों की बात को गम्भीरता से सुनकर निस्तारण किया गया है। उन्होने कहा कि अन्य जनपदों की अपेक्षा इस जनपद में शिकायतों की संख्या कम पायी गई है। उन्होने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि जनपद श्रावस्ती आई0जी0आर0एस0 मामलो के निस्तारण में भी प्रथम स्थान पर आया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी इसके लिए बधाई के पात्र है। उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होने सभी अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि लड़का–लड़की में भेदभाव न करें, दोनों को समान शिक्षा दें, जिससे बेटियां भी अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन करें। उन्होने कहा कि महिलाओं को समृद्ध एवं सशक्त बनाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदैव प्रयासरत है। जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान लायी जा सके। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक उन्हे लाभ दिलाकर उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अमरेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी संजय कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य कर्मचारीगण व पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।

प्राइमरी शिक्षकों के तबादले : यूपी में 15 जून तक कार्यमुक्त होंगे शिक्षक, एडेड में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ (संवाददाता)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर परस्पर तबादला पाने वाले 9272 शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादला पाने वाले शिक्षकों को स्कूल से स्कूल तबादला देने व 15 जून तक कार्यभार व कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि शिक्षकों ने आपसी सहमति के आधार पर तबादले का लाभ लिया है। ऐसे में बीएसए उनके अभिलेखों, विषय, कैडर, पदनाम का परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक व शिक्षिका को ही कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। जिन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, को कार्यवाही समाप्त होने के बाद कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि परस्पर तबादले ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर कार्यमुक्त करने व कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी। तबादला प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता व लापरवाही मिलने पर बीएसए उत्तरदायी होंगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों व शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए। अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार आवेदन 14 जून तक होंगे। प्रबंधन अपनी अनापत्ति देकर आवेदन को 17 जून तक भेजेंगे। डीआईओएस आवेदन का परीक्षण करते हुए 18 जून तक मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इसे 20 जून तक अपर शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की लिखित शिकायत होने पर उसका निस्तारण 23 जून तक होगा। एनआईसी इसके अनुसार 27 जून को तबादला आदेश जारी करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादला पाने वाले शिक्षकों को स्कूल से स्कूल तबादला देने व 15 जून तक कार्यभार व कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि शिक्षकों ने आपसी सहमति के आधार पर तबादले का लाभ लिया है। ऐसे में बीएसए उनके अभिलेखों, विषय, कैडर, पदनाम का परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक व शिक्षिका को ही कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। जिन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, को कार्यवाही समाप्त होने के बाद कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि परस्पर तबादले ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे।

उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं।

उतरौला बलरामपुर भीषण उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं वहीं पर बिजली भी दगा दे गई है। उतरौला नगर में बुधवार को सुब ह पांच बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रही। जिस के चलते लोगों का हाल बेहाल रहा। बिजली के न होने से नगर पालिका परिषद के द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगवाए गए वाटर कूलर का पानी ठंडा नहीं हुआ। इस प्रचण्ड गर्मी में यात्रियों को प्यास की शिद्दत में ठंडा पानी नसीब नहीं हुआ है लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते दिखाई पड़े। यही हाल पेय पदार्थों के दुकान दारों का रहा, बिजली के न रहने से पानी सहित थम्सप, कोका कोला, स्प्राइट मारेण्डा आदि के पेय पदार्थ ठंडा न होने से बिक्री पर असर पड़ा है। आलम यह रहा, कि उमस भरी गर्मी में लोग पसीने से तर–बतर रहे। बिजली के न होने का एहसास कार्यालय में बैठे अधिष्ठ कारियों व वकीलों को हुआ है। लोग बिजली को कोसते हुए रूमाल से पसीना सुखाने पर मजबूर रहे।

जनपद श्रावस्ती शीर्ष 10 जिलों में शुमार-जिलाधिकारी

श्रावस्ती, 11 जून, 2025। सू0वि0। उत्तर प्रदेश सरकार ने माह–मई, 2025 के लिए सी0एम0 डैशबोर्ड की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। यह रैंकिंग जनसुनवाई, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, राजस्व सुधार और समग्र विकास कार्यों के आधार पर तैयार की जाती है। सी0एम0 डैशबोर्ड की समीक्षा में जनपद श्रावस्ती को यू0पी0 में छठवीं रैंक प्राप्त हुई है। मई माह के अन्त में समीक्षा के बाद राज्य के सभी जिलों की रैंकिंग की गयी है जिसमें श्रावस्ती का नाम टाप–10 में शुमार है।

जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी द्वारा सभी विभागों के कार्यों की जमीनी स्तर समीक्षा की गयी और माह– मई, 2025 की समीक्षा में सूबे के टाप–10 में छठवें नम्बर पर जिले का नाम दर्ज करा दिया। जिले को मई महीने की समीक्षा में कुल प्राप्तांक–10 में से 8.96 अंक प्राप्त हुए हैं। जो 89.60 प्रतिशत है। जिले में प्रशासनिक कार्यों, जनसुनवाई, कानून व्यवस्था व जनकल्याणकारी योजनाओं, डेवलपमेंट और राजस्व के बेहतर कियान्वयन के चलते सी0एम0 डैशबोर्ड में यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। माह–मई, 2025 में सी0एम0 डैशबोर्ड पर 27 विभागों के 65 कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी। जिसमें जनपद श्रावस्ती को 50 कार्यक्रमों में ए–श्रेणी प्राप्त हुआ है तथा 27 कार्यक्रमों में प्रथम रैंक मिला है। सी0एम0 डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न झ्च् (की परफार्मेंस इंडीकेटर) की निरन्तर निगरानी की जाती है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसे और दुरूस्त कर नम्बर वन की रैंक लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये सभी विभागों के कार्यो की लगातार समीक्षा की जा रही है।

भीषण गर्मी में टूटा बिजली खपत का इतिहास, एक दिन में सर्वाधिक आपूर्ति का देश में बना रिकॉर्ड

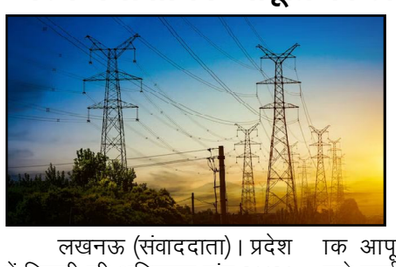

लखनऊ (संवाददाता)। प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 31104 मेगावाट पहुंच गई है। यह देश में सर्वाधिक आपूर्ति का रिकॉर्ड है। इस वर्ष 32 हजार मेगावाट से अधिक मांग होने का अनुमान है। इसके लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को सभी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी व बढ़ती उमस की वजह से बिजली की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में छह जून से बिजली की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अधिकतम मांग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नौ जून की 9.53 बजे बिजली की मांग 31059 मेगावाट थी, जो रात 11 बजे बढ़कर 31,104 मेगावाट तक पहुंच गई। पिछले वर्ष बिजली की सर्वाधिक मांग 30,618 मेगावाट तक पहुंची थी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बताया कि नौ जून को गुजरात में 25,230 मेगावाट, महाराष्ट्र में 25 191 मेगावॉट, तमिलनाडु में 17,867 मेगावाट, राजस्थान में 16,562 मेगावॉट, पंजाब में 15,508 मेगावॉट विद्युत की सर्वाधिक आपूर्ति की गई। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकार्ड कायम किया है। पिछले तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आपूर्ति कर रहा है। उन्होंने सभी विद्युत कर्मियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

गांवों में 12 घंटे ही मिल रही बिजली

सीतापुर (संवाददाता)। गर्मी बढ़ते ही बिजली की खपत बढ़ गई है। शहर से लेकर गांव तक आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई है। शहर में तीन से चार घंटे व गांवों में 10–14 घंटे की लंबी कटौती हो रही है। रोस्टर फॉलो कर पाना बिजली विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है। रामपुर मथुरा इलाके के बांसुरा उपकेंद्र से जुड़े 300 से अधिक गांवों में मुश्किल से आठ से 10 घंटे ही बिजली सप्लाई होती है। वोल्टेज इतना कम होता है कि पंखे चलना भी मुश्किल रहता है। एसडीओ विजय गोयल के अनुसार अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। कंदुनी उपकेंद्र से जुड़े 350 गांवों में रोस्टर के हिसाब से आपूर्ति नहीं हो रही है।

उपभोक्ता की दुनिया
साध्य हिन्दी दैनिक
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शारदा प्रसाद पाठक द्वारा शंकर प्रिंटिंग प्रेस निकट भरत मिलाप चौराहा, नई बाजार भिनगा से मुद्रित तथा ग्राम हन्नामार पोस्ट गिलौला जनपद श्रावस्ती उ0प्र0 से प्रकाशित।
सम्पादक
भगवान दीन पाठक
मो0– 91 94504 54367,
91 96530 13722
सभी विवादो का न्याय क्षेत्र श्रावस्ती होगा।